







# संपादकीय



## संसद की गरिमा कायम रखना सत्तापक्ष के साथ विपक्ष की भी जिम्मेदारी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों के नकारात्मक रूपे को का संकेत करते हुए यह कहा कि वे अभी भी पुराने ढाँचे पर चल रहे हैं और न तो खुद कछु करना चाहते हैं और न ही दूसरों को करने देना चाहते हैं, उससे इन्कार करना कठिन है। नकारात्मक का कारण न होना सत्र बाधित है। विपक्ष एक और तो मणिशुर की घटासों को लेकर बहुत ही चिंतित और व्यथित नजर आ रहा है, लेकिन वह उस पर संसद में सार्थक चर्चा भी नहीं होने दे रहा है।

यह समझना कठिन है कि दिल्ली में सेवाओं संबंधी विधेयक रूप विपक्ष ने जिस तरह लोकसभा की चर्चा में भाग लिया, उसी तरह वह अन्य विधेयकों के पेश और पारित होने में सहभाग लिया चाहता है। संसद तभी सत्तापक्ष और विपक्ष, दोनों के बीच कोई समझाव और सम्झन्य कायम हो, तोकिन पिछले कुछ समय से यह देखते हीं में आ रहा है कि सत्तापक्ष और विपक्ष किसी भी मान्यते पर एकत्र करने नहीं आते। यही कारण है कि संसद में सार्थक बहस का अभाव बढ़ता चला जा रहा है।

बात केवल मानवून सत्र में ही रहे हांगामे की ही नहीं है, उसके पहले भी जो सर हुए, उनका अधिकारिंश दिस्सा गतिरेख और हांगामे की भेंट चढ़ गया। यहां तक कि बढ़त सर में भी हांगामा ही होता रहा। बढ़त सर के दोरान इतना अधिक हांगामा हुआ कि बोना चर्चा की ही पारित करना पड़ा। मोदी सरकार के इस कार्यकाल में यह सम्पर्ण करना कठिन है कि विपक्षक पर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच गहन-विस्तृत चर्चा हुई थी।

विपक्ष को यह समझना चाहिए कि विरोध के लिए विरोध की राजनीति से वह अपना ही नुकसान कर रहा है। बानसून सत्र में विपक्षी दलों ने जैसा लेया दिया था, उससे आम दलों की बीच यही संदेश गया कि वे जानवरकर संसद को नहीं चलते देना चाहते हैं। विपक्षी दलों को यह समझना चाहिए कि संसद में यह चलते हीं लिलने वाला इसके विपरीत आम जाता यह देख-समझ रही है कि उनको नकारात्मक राजनीति कई अहम मसलों पर समाधान निकलते में बाधक बन रही है।

विपक्ष अपने इस रूपे के पोछे चाहे जैसे तर्क दे, लेकिन उसे इसकी अनुभूति होनी चाहिए कि संसद की गरिमा और महत्व कायम रखने के लिए उसकी भी उत्तरी ही जिम्मेदारी है जितनी कि संसद की। संसद की गरिमा और विपक्ष में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन लोकतंत्र तो मतभेदों के बीच सम्झन्य कायम करने की विधि है। विपक्ष में संसद-परिषद् और विपक्ष में सामंजस्य की अवाव इसी रह बहुत रहा तो इससे केवल संसद की गरिमा ही नहीं गिरेगी, बल्कि पक्ष-विपक्ष के बीच राजनीतिक लाभ नहीं मिलने वाला। इसके विपरीत आम जाता यह देख-समझ रही है कि उनको नकारात्मक राजनीति कई अहम मसलों पर समाधान निकलते में बाधक बन रही है।







